



सिंगल कॉलम

अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ी



नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत साई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चन्द्रप्रति सिंह की न्यायिक हिरासत साई तक बढ़ा दी है। बीती 15 अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबोजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को राहत, झामुमो की संपत्तियों की जांच पर रोक



नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्तियों की जांच पर भारत के लोकपाल को 10 मई तक कोई भी कदम उठाने पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल के समक्ष शिवालय दायर करने वाले भाजपा सांसद नरेशनाथ द्वेड़ को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है। लोकपाल ने अपने आदेश में झामुमो के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 मई को आगे की सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में लोकपाल को देने की अमृत है। हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख यानी 10 मई तक लोकपाल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। उपर दिकी हाइकोर्ट में झामुमो की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिखल और अरुणाभ चौधरी पेश हुए। उन्होंने कहा कि दोनों संपत्तियां राजनीतिक दल की हैं, सोरेन की नहीं। यह भी तर्क दिया गया कि चार मार्च का आदेश लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम के तहत भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से परे था। कपिल सिखल ने कहा कि कानून के तहत जांच केवल एक व्यक्ति के खिलाफ ही शुरू की जा सकती है, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं।

भ्रष्टाचार मामले में ओडिशा के विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा निलंबित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीमी की सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सूय कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली विधायक की याचिका पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील को सुनने और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सजा निलंबित करने को आदेश दिया जाता है। विधायक मोहम्मद मुकीमी को बिजिलेंस कोर्ट द्वारा 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया था। बिजिलेंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुकीमी ने मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रहते हुए एक आईएएस अफसर के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट फर्म को फायदा पहुंचाया था। उस दौरान कोर्ट ने विधायक को तीन साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद मोहम्मद मुकीमी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी लेकिन दस अप्रैल को कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी।

आचार संहिता के दौरान 5वां दौरा: प्रधानमंत्री आज सागर
और हरदा में करेंगे सभा, इसके बाद भोपाल पहुंचेंगे
**पीएम मोदी आज भोपाल में करेंगे रोड
शो, सीएम मोहन बोले- बनेगा रिकॉर्ड**

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्यप्रदेश के दौर पर रहेंगे। पीएम मोदी आचार संहिता के दौरान 5वीं बार बुधवार को सागर और हरदा में सभ करने के बाद भोपाल में रोड शो करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाला रोड शो ऐतिहासिक होगा और चुनाव के दौरान पीएम के एमपी दौरे का रिकॉर्ड भी बनेगा। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मोदी का रोड शो एक किमी का होगा। रोड शो में 200 से अधिक मंचों पर अलग-अलग प्रकार से पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। कलाकार, साधु-संत, अलग-अलग वर्गों के लोग पीएम मोदी का स्वागत रोड शो में करेंगे। भोपाल दुल्हन की तरह सजेगा। बंगाली समाज की बहनें शंख ध्वनि के साथ अभिनंदन करेंगी। व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठान से पीएम मोदी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। सांस्कृतिक झांकियां भी रहेंगी।

पीएम मोदी ने मप्र को दी सवा लाख करोड़ की सीगारें- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी तरह के संसाधनों पर हक देश के सभी वर्ग के लोगों का है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में वर्ग विशेष के लिए संसाधनों पर हक की बात लिखकर निंदनीय काम किया है। इसके लिए कांग्रेस को देश के सभी वर्ग के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की ओर से मध्य प्रदेश को दी गई



सौगातों का हिसाब लगाएँ तो पता चलता है कि सवा लाख करोड़ की सौगातें मिली हैं। सौ दिन में पार्वती-काली सिंध-चंबल नदी परियोजना और केन-बेतवा परियोजना की सौगात पीएम मोदी ने दी है।

फसल कटाई के कारण पहले दौर में कम वोटिंग- वोटिंग कम होने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अप्रैल में चुनाव हुए हैं जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में मई में वोटिंग हुई थी। इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है और शादी विवाह का सीजन भी है। इसलिए वोटिंग कम हुई है। साध्वी

प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार में न आने को लेकर कहा कि वे प्रचार करने जाएंगी। पीएम मोदी के भोपाल आने को लेकर कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के बीच वोट मांगने के लिए आना पीएम मोदी की विनम्रता का परिचायक है।

आठ माह में दूसरी बार सागर आ रहे हैं पीएम- सागर में पीएम के कार्यक्रम को लेकर मकरोनिया इलाके के बड़तूमा में सभास्थल पर पंडाल लगाने का काम चल रहा है। पीएम मोदी आठ माह में दूसरी बार बड़तूमा आ रहे हैं इससे पहले 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर का भूमिपूजन करने आए थे।

**पीएम मोदी का तंज, कहा- कांग्रेस की लूट
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी**

अंबिकापुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी ने आँकड़ापुर में स्थानीय कलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के प्रवास को दृढ़तापूर्वक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। आँकड़ापुर की सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरगुजा के साथ ही कोरबा और रायगढ़ साइड सीट के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। कुछ माह पहले मैंने आपसे कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था, आपने मेरी बात का मान रखा और भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। विपक्षदेव साथ विकास के लिए तेजी से काम कर रहे, लेकिन इन्होंने कम समय में रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन



कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है, इतना ही नहीं जो लोग निर्दोषों को मार रहे हैं, पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमला करते हैं वे मारे जाएं तो कांग्रेस ऐसे लोगों को शहीद कहती है। इसी कांग्रेस का सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है जब मैं विकसित भारत कहता हूं, तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गरम हो जाता है अगर भारत शक्तिशाली हो गया, तो कुछ

ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया, तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं जब संविधान बन रहा था तब बाबा साहेब ने कहा था धर्म के आधार पर नहीं होगा पर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डालकर भारत के सामाजिक न्याय और

सेक्युलरिज्म कांग्रेस संविधान बदलकर एससी-एसटी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता-पिता से मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाएगी। आप जे अपनी संपत्ति बनाते हैं वो आपके बच्चे को नहीं मिलेगी। उसे कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बावजूद भी हमारा देश संस्कार और संस्कृति से उपभोक्तावादी नहीं बन रहा है। हम संस्कृति करने में विश्वास करते हैं। हम मेहनत करके जीने वाले लोग हैं भारत में। यह भारत का मूलभूत संस्कार है। कांग्रेस इसे मिटाने की सोच रही है। आप को आपका बेटा है। आपका इलाज करने की सोच रही है। पहाड़ी कोकवाड़ा, माड़ी मझवरा जैसी जनजाति

9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार मुकदमे को किया खारिज

सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने रहेंगे दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक नेता

मुंबई। 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैयदाना मुफहल सैफुद्दीन को राहत दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊदी बोहरा शिया समुदाय के नास (उत्तराधिकारी) पद को लेकर मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। पीठ ने सैयदाना मुफहल सैफुद्दीन के भतीजे सैयदाना ताहर फखरुद्दीन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सैयदाना मुफहल सैफुद्दीन के उत्तराधिकारी पद को चुनौती दी गई थी। याचिका में ताहर ने दावा किया था कि असली उत्तराधिकारी वे हैं और दाऊदी बोहरा समुदाय की सभी चल और अचल संपत्ति पर उनका हक है। उन्होंने अदालत से यह भी मांग की थी कि सैयदाना मुफहल

सैफुद्दीन को समुदाय की किसी भी संपत्ति में घुसने न दिया जाए। हालांकि अदालत ने मुफद्दल उतराधिकारी की उपाधि को सही पाया है। **9 साल तक चला मुकदमा-** 2014 में 52वें सैयदान मोहम्मद बुरहानुद्दीन का निधन हो गया और उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन 53वें सैयदान बने। सैयदान बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने सैफुद्दीन के उतराधिकार को चुनौती देते हुए दावा किया कि सैयदान बुरहानुद्दीन ने 1965 में गुप्त रूप से उन्हें उतराधिकार की आधिकारिक घोषणा नास प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि सैफुद्दीन ने सर्जरी तरीके से सैयदान का पद संभाला था। कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि

1965 में बुरहानुद्दीन के दाई बनने के बाद, उन्होंने 10 दिसंबर, 1965 को माजून की घोषणा से पहले, सार्वजनिक रूप से कुतुबुद्दीन को माजून (दूसरी कमान) के रूप में नियुक्त किया था और एक गुप्त नास के माध्यम से निजी तौर पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। नौ साल तक चलने वाले फैसले को अप्रैल 2023 में सुक्ष्म रखा गया। अंतिम सुनवाई नवंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में समाप्त हुई।

केवल अंतिम नाम मान्य- कुतुबुद्दीन का 2016 में निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन ने कानूनी लड़ाई जारी रखी और 54वें दाई के रूप में मान्यता मांगी। फखरुद्दीन ने

दावा किया कि उनके कुतुबुद्दीन ने उन्हें नास की प्रदान की थी। अलात ने की स्थिरता, वैध नास आवश्यक्ताएँ, क्या मूल कुतुबुद्दीन और उसके काबे बेटे फखरुद्दीन को वैध नास किया गया था, क्या नास सकिता था, सकिता है या ब न सकिता है, सकिता पाँच र किए। क्या प्रतिवादी सैफु वैध नास प्रदान किया ग फखरुद्दीन के वकील आन ने तर्क दिया कि एक बा किया गया नास स्थायी है बदला नहीं जा सकता है विपरीत, बचाव पक्ष (सै के लिए वरिष्ठ वकील द्वारकादोस ने जोर देकर नास को बदला जा सकता

भले ही कृतबुद्धीन को नास प्रदान किया गया हो, केवल अंतिम नास मान्य होगा जो सैफुद्दीन को प्रदान किया गया था। बचाव पक्ष न दावा किया कि 52वें दार्द बुरहानुद्दीन ने 4 जून, 2011 को गवाहों की उपस्थिति में अपने बेटे सैफुद्दीन को नास प्रदान किया था। बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया कि 20 जून, 2011 को सैफुद्दीन को सार्वजनिक रूप से उत्तराधिकारी-नामित के रूप में पुष्टि की गई थी।

जानें सैयदना मुफहल सैफुद्दीन के बारे में सैयदना मुफहल सैफुद्दीन 53वें अल-दाई अल-मुतलक और विश्वव्यापी दाऊदी बोहरा समुदाय के वर्तमान नेता हैं। सैयदना सैफुद्दीन दुनिया भर में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें

उनकी आस्था, संस्कृति और विरासत के करीब लाते हैं। गौतमलख हैं, दाऊदी बोहरा, शिया समुदायों के बीच एक धार्मिक समुदाय है। वह परंपरिक रूप से व्यापारियों और उद्यमियों का समुदाय है, जिसके भारत में पाँच लाख से अधिक सदस्य हैं और दुनियाभर में 10 लाख से अधिक हैं। समुदाय के शीर्ष धार्मिक नेताओं को सद्दा-अल-मुतलक के नाम से जाना जाता है। दाऊदी बोहरा सिद्धांत के अनुसार, एक उत्तराधिकारी को ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। समुदाय के किसी भी योग्य सदस्य को नास (उत्तराधिकार प्रदाता) करना प्रदान किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि वर्तमान दाऊदी परिवार का ही सदस्य हो।

इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, सतना, सागर, रीवा, कटनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, गुना, सीधी, उमरिया, छग, उप्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं नई दिल्ली से प्रसारित

सिंगल कॉलम

इंदौर में निर्माणाधीन स्कूल की पांचवीं मंजील से गिरने से मजदूर की मौत

इंदौर। शहर के तलावली चांदा स्थित डीसी मेमोरियल स्कूल बिल्डिंग पर मंगलवार को जुगाड की लिफ्ट से सामान ऊपर चढ़ाया जा रहा था। इस दौरान ऊंचाई से गिरने से मजदूर कमल सोलंकी घायल हो गया। नंदन नगर निवासी कमल को तुरंत परिजन एमवाय हास्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां आने से पहले ही कमल की मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा गया है। वृद्धा से चैन लूटी लसुड़िया थाना क्षेत्र में बाइक सवारों ने 63 वर्षीय वृद्धा से सोने की चैन लूट ली। बदमाश फोन पर बात करने के बहाने आए थे। पुलिस के मुताबिक घटना स्कीम-144 में पुष्पा गोठवाल के साथ रात करीब साढ़े दस बजे हुई है। एक बदमाश फोन लेकर आया और कहा कि बात कर लो। महिला कुछ समझती इसके पूर्व झपड़ा मारकर चैन तोड़ ली।

अगस्त तक सेवानिवृत्ति वालों को मिलेगी चुनाव ड्यूटी से छूट

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति के छह माह शेष हैं। इस आदेश के साथ बड़ी संख्या में जिला निर्वाचन कार्यालय के पास चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के आवेदन पहुंच रहे हैं। इनमें दिसंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के आवेदन भी आ रहे हैं, जबकि आचार संहिता लागू की तारीख से छह माह की गणना की जाएगी। इसके अनुसार, अगस्त तक सेवानिवृत्ति वालों को ही चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। अन्य को चुनाव ड्यूटी करना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के पास 125 आवेदन सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के पहुंचे हैं। सभी में चुनाव ड्यूटी से छूट मांगी गई है। इनमें दो दर्जन के करीब आवेदन नवंबर और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वालों के हैं। इनको चुनाव कार्य से मुक्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद अगस्त तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को ही चुनावी कार्य से मुक्त करने का निर्णय लिया है। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के समय से छह माह की गणना की जा रही है। इसके अनुसार ही चुनाव कार्य से कर्मचारियों और अधिकारियों को मुक्त रखा जा रहा है।

360 का अवकाश स्वीकृत चुनावी ड्यूटी के दौरान विवाह और अन्य आयोजन होने के कारण 360 के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं। यह सभी आयोजन के बाद चुनावी कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे। 190 आवेदन गंभीर बीमारी के प्राप्त हुए। इनमें से 111 को चुनाव कार्य से मुक्त किया जा चुका है। यह गंभीर बीमारी के कारण चुनाव कार्य करने में असमर्थ थे। 900 डबल ड्यूटी के आवेदन जिला निर्वाचन विभाग के पास 1800 के करीब आवेदन चुनाव कार्य से मुक्त रखने और डबल ड्यूटी के पहुंचे हैं। इसमें 900 के करीब आवेदन डबल ड्यूटी से संबंधित हैं। इनकी ड्यूटी एक से अधिक कार्यों में लग गई थी। अब सभी को एक ड्यूटी दी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही निर्वाचन कार्यालय सभी तरह के अवकाश के आवेदन पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला है। सिर्फ आकस्मिक अवकाश में ही छूट दी जाएगी।

इंदौर में डिवाइडर से टकराकर खंभे में घुसी बाइक

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में सोमवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उसकी बाइक डिवाइडर से टकराकर खंभे में जा घुसी थी। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। घटना देर रात पिपलिया राव की है। मूलतः कृष्णा कालोनी नरोजा बागमुंडी उमरिया निवासी सुमित वर्मन स्कीम-78 क्षेत्र में रहता था। एमबीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी तलाश रहा था। उसके दोस्त शादी समारोह में बाहर गए थे। सोमवार रात सुमित दोस्तों के पास भंवरकुआं क्षेत्र में गया था। रात को वह काम से जा रहा था तो तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा कर खंभे में घुस गई। सुमित को राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया लेकिन उसकी मौत हो गई। सुमित के पिता शंकर दयाल वर्मन कोल कंपनी में अधिकारी है।

नामांकन के नाम पर नए वकीलों से वसूली जा रही मोटी राशि को लेकर बहस पूरी

सिटी चीफ इंदौर।

राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नए वकीलों से नामांकन शुल्क के नाम पर वसूले जा रही 20350 रुपये की राशि को चुनौती देने वाली याचिका में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इसे अप्रैल के अंत में जारी करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि नए वकीलों को परिषद द्वारा वसूले जा रहे भारी-भरकम नामांकन शुल्क से राहत मिलेगी या नहीं। याचिका मप्र हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, लेकिन बार काउंसिल आफ इंडिया के आवेदन के बाद इसे सुप्रीम ट्रांसफर कर दिया गया।

याचिका एडवोकेट निमेष पाठक व अन्य ने दायर की है। याचिका में कहा है कि एडवोकेट एक्ट के प्रविधानों के तहत राज्य अधिवक्ता परिषद नामांकन



शुल्क के रूप में सिर्फ 750 रुपये ले सकते हैं, लेकिन मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद 20350 रुपये ले रहा है। हर वर्ष

हजारों की संख्या में नए वकील राज्य अधिवक्ता परिषद के समक्ष नामांकन के लिए आवेदन करते हैं। वर्तमान में

विधि की पढ़ाई अत्यंत महंगी होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ाई पूरी करना मुश्किल हो गया है। ये विद्यार्थी जैसे-तैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नामांकन के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद के समक्ष जाते हैं तो उन्हें नामांकन के नाम पर मोटी राशि देना होती है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बंसंत ने तर्क रखा कि बार काउंसिल कल्याणकारी उपायों के लिए योगदान की आड़ में वैधानिक रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि जमा नहीं कर सकते। यह उन युवा वकीलों के लिए मुश्किल खड़ी करने जैसा है जिन्होंने अब तक कमाई ही शुरू नहीं की। बार काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से तर्क रखा गया कि नामांकन

शुल्क के रूप में 750 रुपये की राशि वर्ष 1993 में तय की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि नामांकन शुल्क बढ़ाना संसद का काम है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह है मुख्य मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में चल रही अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस आफ इंडिया डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ में हुई। इन याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या बार काउंसिल एडवोकेट्स अधिनियम 1961 की धारा 24 (1) (एफ) के अनुसार निर्धारित नामांकन फीस (राज्य बार काउंसिल के लिए 600 रुपये और बार काउंसिल आफ इंडिया के लिए 150 रुपये) से अधिक शुल्क वसूल सकती है।

सुरों ने थाम रखी प्रचार और मतदाता जागरूकता की कमान

राऊ-महू के बीच रेलवे रूट पर दौड़ेगा करंट

सिटी चीफ इंदौर।

शहर में लोकसभा चुनाव की सरगमियां बढ़ रही हैं। प्रत्याशी और कंपनियां लोगों के बीच अपना प्रचार और मतदाता जागरूकता के लिए गाने शूट करवा रहे हैं। इंदौर में ही इंदौर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, राजगढ़ आदि लोकसभा प्रत्याशियों के लिए गाने शूट किए गए हैं। सरकारी और निजी कंपनियां इंदौर को मतदान में नंबर 1 बनाने के प्रयास के लिए विभिन्न जागरूक कार्यक्रम चला रहीं हैं। गायक कपिल पुरोहित ने बताया कि तरह-तरह गानों को रिकार्ड करवाकर जनता को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। गाने रिकार्ड करवाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों में होड़ लगी है। कांग्रेस के गानों में लोकल क्षेत्र का नाम तो बीजेपी के गानों में हिंदू धर्म का गुणगान प्रमुखता से दिख रहा है। गायक पवन भाटिया ने बताया कि मतदान जागरूकता के लिए कई गाने रिकार्ड हो रहे हैं। करीब 29 अप्रैल तक कुछ गाने रिलीज होंगे। वहीं प्रोड्यूसर संजय बिंदल ने बताया कि प्रशासन के साथ कई निजी कंपनियां भी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। मतदान की अपील के लिए गाने रिकार्ड हो गए हैं। अब उस पर काम हो रहा है। जल्द ही जागरूकता



गाने लांच किए जाएंगे।

अधिकारी की आवाज से मतदान के लिए जागरूक हो रहे

जिला प्रशासन लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए %इंदौर तैयार है गाने को जिला गान के रूप में प्रयोग कर रहा है। कमाल की बात यह है कि इस गाने को किसी प्रोफेशनल नहीं बल्कि अधिकारी

सिद्धार्थ जैन ने गाया है। सिद्धार्थ जैन जिला पंचायत में सीईओ हैं। जैन ने बताया कि मुझे गाने का पहले से ही शौक था। जिले में चुनाव का माहौल बना और लोगों को संगीत के जरिए मतदान के प्रति जागरूक करने की योजना बन रही थी। तब मुझे गाने का मौका। यह अनुभव मेरे लिए शानदान रहा।



सिटी चीफ इंदौर।

राऊ से महू के बीच दोहरी लाइन बिछाई जा रही है। इस दूसरी लाइन में एक मई से करंट दौड़ने वाला है। 25 हजार वाट के करंट को तारों में प्रभावित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए लाइन से दूर रहने के लिए कहा है। इसके बाद मेगा ब्लाक लेकर दोहरी लाइन पर ट्रेन दौड़ा कर परीक्षण किया जाएगा।

राऊ से महू के बीच 9.50 किमी लंबे रेल रुट का दोहरीकरण किया जा रहा है। इस रूट पर रेल की पटरियां बिछाने के साथ ही बिजली से जुड़े काम भी पूरे हो चुके हैं। एक मई से इस रेल रूट की लाइन को चार्ज किया जाएगा। रेलवे द्वारा क्रासिंग पर बैरियर लगाए हैं, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके।

मिलावटी खाद्य पदार्थ की आशंका होने पर आप ऐसे कर सकते हैं जांच



सिटी चीफ इंदौर।

खाद्य पदार्थों को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो खाद्य पदार्थों की घर पर भी स्वयं जांच कर सकते हैं। इसकी जांच के लिए यूट्यूब पर डीएआरटी एफएसएसएआइ द्वारा अलग-अलग खाद्य पदार्थों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इनके माध्यम से आसानी से पता कर

सकते हैं, वहीं किसी भी खाद्य विभाग की मिलावट की शंका है तो वाट्सएप 9406764084 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भी नहीं बताना चाहते हैं एमपीएफडीएमआइएस .इन पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी शिकायत की जा सकती है।

शराब भरते ट्रक के फुटेज जब्त, घरे में विधायक का करीबी ठेकेदार

सिटी चीफ इंदौर।

लाखों रुपये कीमत की शराब तस्करी के तार ठेकेदार से जुड़ गए हैं। पुलिस ने शराब भरते हुए ट्रक के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। दुकान भाजपा विधायक के करीबी ठेकेदार की है। एक कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर फरार है। एरोड्रम पुलिस ने सुपर कारिडोर से 300 पेट्री शराब से भरा ट्रक पकड़ा था। सोमवार को आरोपित अजय चौकसे, आकाश वर्मा और मनोज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अजय ने शराब ठेकेदार का नाम कबूला है जो भाजपा विधायक का करीबी है। अजय ने बताया कि ट्रांसपोर्टर जीतू राठौर के ट्रक का बंदोबस्त किया था। मनोज ने ऐसा ट्रक मुहैया करवाया जो अहमदाबाद (गुजरात) माल लेकर जा रहा



था।अजय ने बायपास (कनाडिया) स्थित दुकान से दोपहर में ही ट्रक में 300 पेट्रियां भरवा दी। पुष्टि के लिए पुलिस ने शराब दुकान के समीप स्थित टाइल्स की दुकान से डीवीआर

जब्त कर लिया। फुटेज में ट्रक के साथ एक कार जाते हुए नजर आई जो कर्मचारी मनीष की थी। डीसीपी जोन-1 विनोद कुमार मीना के मुताबिक, तीनों आरोपितों को रिमांड पर लिया

गया है। पुलिस मुख्य आरोपित के करीब पहुंच चुकी है। तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। गुजरात के शराब तस्कर को भी चिन्हित कर लिया जो अजय के जरिए शराब मंगवाता था।

दुकान का डीवीआर जब्त करेगी पुलिस

हाईप्रोफाइल केस की जांच जोन-1 के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा की निगरानी में चल रही है। आरोपितों को भी तेजाजी नगर थाना में रखा गया है। उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक पुलिस शराब दुकान का डीवीआर भी जब्त करेगी। अजय ने यह भी बताया कि वह करोड़ों रुपयों की शराब गुजरात में सप्लाई कर चुका है।

नगर निगम के दस्तावेजों को आनलाइन करने की कवायद शुरू

सिटी चीफ इंदौर।

28 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जी बिल प्रस्तुत होने और इसमें से तीन करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान होने के बाद नौद से जागा इंदौर नगर निगम अब निविदा की पूरी प्रक्रिया को आनलाइन करने जा रहा है। इसके अलावा निविदाओं के दस्तावेजीकरण भी आनलाइन होगा। इसके अलावा पुरानी निविदाओं और उनके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को भी आनलाइन किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए आइट्टी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। महापौर पुण्यमित्र भार्गव ने बताया कि दस्तावेजों को आनलाइन करने की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। 100 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा होने की आशंका इधर 28 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जी बिल प्रस्तुत होने के मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को करीब चार



करोड़ रुपये के एक दूसरे फर्जीवाड़े के दस्तावेज हाथ लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि नगर निगम में 100 करोड़

रुपये से अधिक का भुगतान बगैर किसी काम के ठेकेदारों को हो चुका है। मंगलवार को जिस चार करोड़ रुपये के

फर्जीवाड़े की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है उसे अंजाम देने वाले ठेकेदार के तार एक कांग्रेसी नेता से जुड़े होने की

बात भी पता चली है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 28 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जी बताए जा रहे बिल और दस्तावेजों पर निगम के जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर थे उन्हीं के हस्ताक्षर चार करोड़ के नए फर्जीवाड़े में भी दस्तावेजों पर पाए गए हैं। आशंका है कि नगर निगम में बगैर काम के फर्जी बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करने का खेल करीब दस वर्षों से चल रहा है। इस दौरान 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कथित ठेकेदारों को हो भी चुका है।

इधर वेतन के लाले, उधर बगैर काम के ठेकेदार ले रहे करोड़ों

नगर निगम की आर्थिक स्थिति को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। कई बार नगर निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक की व्यवस्था नहीं रहती। इधर दूसरी तरफ कथित ठेकेदार बगैर काम के करोड़ों का भुगतान निगम से ले रहे हैं।

भोपाल जेल में कैदियों का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उपचार, हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों ने दी सेवाएं

सिटी चीफ भोपाल। केंद्रीय जेल भोपाल में मंगलवार को पहली बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कैदियों को उपचार किया गया। इससे जेल की व्यवस्था भी बनी रहेगी, साथ ही कैदी जेल से बाहर जाए बिना उपचार प्राप्त कर सकेगा। वहीं सिपाही का भी कैदी को अस्पताल ले जाने, वापस लाने का समय बचेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सहयोग से जेल में परिरुद्ध कैदियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टेली मेडिसिन कैंप आयोजित हुआ। इस दौरान हमीदिया चिकित्सालय के चिकित्सकों ने कैदियों का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपचार किया।

इनका किया उपचार

टेली मेडिसिन स्वास्थ्य शिविर के द्वारा जेल में 10 दंडित कैदी, 12 विचाराधीन कैदी, छह महिला कैदी एवं एक बच्चे सहित कुल 28 महिला-पुरुष कैदी एवं उनके साथ परिरुद्ध एक बच्चे का जो चर्म रोग से ग्रसित थे, उनको चिकित्सक द्वारा परीक्षण कर उपचार के बारे में बताया गया।

जेल में ही हुई कैदियों की स्वास्थ्य जांच



जेल अधीक्षक राकेश कुमार भारंगे ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जेल में ही कैदियों की जांच की, जिससे चिकित्सालय जाने के दौरान अतिरिक्त सिपाहियों का समय भी बचा।

आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने में ग्वालियर अटवल

सिटी चीफ भोपाल। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने में ग्वालियर जिला सबसे आगे है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हुई और तब से लेकर अब तक तीन हजार 757 शिकायतें सी विजिल एप पर हो चुकी हैं। इसमें सर्वाधिक 381 ग्वालियर जिले की हैं। इनका निराकरण कर संबंधितों को सूचित भी किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि नागरिक को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करने की सुविधा दी गई है। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट में कार्रवाई की जाती है। अब तक जो शिकायतें



प्राप्त हुई हैं, उन सभी का निराकरण किया जा चुका है। इसमें शिकायतकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाती है। अभी तक एप पर तीन हजार 757 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें सागर में 295, उज्जैन

257, दमोह 224, मुरैना 184, राजगढ़ 177, रीवा 166, इंदौर 159, सीहोर 119, खरगोन 112, नरसिंहपुर 109, कटनी 06 और सतना जिले में 104 शिकायतें मिली हैं।

मप्र में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने का 25 अप्रैल अंतिम दिन

सिटी चीफ भोपाल। प्रदेश में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 25 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि तक जो भी व्यक्ति नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो जाएगा, उनके नामांकन पत्र लिए जाएंगे। 26 अप्रैल को इनकी जांच होगी और 29 अप्रैल तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि चौथे चरण के लिए मंगलवार को 11 अभ्यर्थियों ने 15 नाम नामांकन पत्र जमा किए। इनमें उज्जैन में दो,



मंदसौर में एक, रतलाम में दो, धार में एक, इंदौर में दो, खरगोन में एक और खंडवा में दो अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। देवास लोकसभा के लिए

मंगलवार को किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र जमा नहीं किया गया। इस प्रकार अब तक 39 अभ्यर्थियों द्वारा 62 नामांकन पत्र जमा किए जा चुके हैं।

भोपाल में 22 उम्मीदवार, 2097 केंद्र पर लगेगे 5442 बीयू

सिटी चीफ भोपाल। लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र भोपाल में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में अब मतदान केंद्रों पर बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। दरअसल 16 से अधिक उम्मीदवार होने के कारण प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो-दो बीयू लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव आयोग से 1400 अतिरिक्त बीयू मांगी थी। आयोग ने यह उपलब्ध करा दी है। ये यूनिट बुधवार को रायसेन जिले से आएंगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन्हें रखा जाएगा। भोपाल लोकसभा से 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जबकि 2097 मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 20 प्रतिशत बैलेट यूनिट अलग से रखी जाती है, ताकि गड़बड़ी होने पर उसे तत्काल



बदल दिया जाता है। यदि 16 से कम उम्मीदवार होते तो भोपाल में 2621 बैलेट यूनिट की जरूरत होती लेकिन इस बार उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने से दोगुनी यानी 5442 बीयू की जरूरत होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस समय जिला निर्वाचन कार्यालय के पास करीब 4,000 बैलेट यूनिट हैं।

अखाड़ा महासंघ के चल समारोह में युवाओं ने किया शौर्य का प्रदर्शन

सिटी चीफ भोपाल। राजधानी में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व पूर्ण श्रद्धाभाव और धूमधाम से मनाया गया। इस पावन मौके पर पुराने शहर में श्री हिंदू अखाड़ा महासंघ द्वारा परंपरा अनुसार चल समारोह निकाला गया। इसमें शहर के 10 अखाड़े शामिल हुए। शोभायात्रा के दौरान अखाड़े के पहलवानों के अलावा युवतियों ने भी शौर्य भरे करतब दिखाए। जलूस रात



नौ बजे छोला क्षेत्र स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां ध्वजा चढ़ाने के बाद आरती की गई।

मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा : गांव-गांव कैसे चलें बस, लोक परिवहन की दरकार

सिटी चीफ भोपाल। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा और रोजगार की। इन सब में कोई राज्य तभी आगे निकल सकता है जब लोक परिवहन की सुविधा दुरुस्त हो। सस्ती, सुगम, सुरक्षित और त्वरित परिवहन की सुविधा उन्हें मिल सके। प्रदेश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। उन्हें उपचार के लिए आयुष्मान योजना की सुविधा मिल रही है। आरटीई के अंतर्गत अच्छी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की सुविधा भी मिलती है, पर कहीं आने-जाने के लिए वह निजी बस या अन्य साधनों में मनमानी किराया देने को मजबूर हैं। लोक परिवहन के माध्यम से गांव-गांव तक बसें चलाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब सरकार हर स्तर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए। लोक परिवहन के क्षेत्र में काम कर रहे जानकारों का कहना है कि रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट में साफ लिखा है कि, नो प्राफिट, नो लास के आधार पर आमजन को परिवहन सुविधा मिलनी चाहिए, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा इसी आधार पर उपलब्ध करा रही है। एक कल्याणकारी राज्य में परिवहन सुविधा भी

इसी प्रकार से मिलनी चाहिए। यही कारण है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में लोक परिवहन के सरकार के हाथ में है। मप्र में सरकार ने राज्य परिवहन निगम को दो जनवरी 2005 को बंद करने की घोषणा की थी। 2010 के बाद से बसों का संचालन बंद हो गया था। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि बस चलाने में घाटा हो रहा है, जबकि उन्हीं रूटों पर निजी आपरेटर अब कमाई कर रहे हैं। प्रदेश में 15 हजार बसों को मिलाकर लगभग डेढ़ लाख वाहनों का संचालन निजी आपरेटर कर रहे हैं। उनकी निगरानी ठीक से नहीं होने के कारण वह परमिट किसी और रूट की लेते हैं पर वाहन अधिक लाभ वाले रूट पर चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ब्लाक, तहसील या जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए यह कर सकती है सरकार मध्य प्रदेश में 55 हजार से अधिक गांव हैं। इनमें लगभग 10 प्रतिशत को छोड़ दें तो मुख्य सड़क से तीन से 10 किमी तक दूर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी जगह डामर की सड़कें बन गई हैं, पर यहां के ग्रामीणों को अपने साधन या पैदल चलकर ही मुख्य सड़क तक आना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा के लिए काम करने



वाले संगठनों ने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि सरकार पंचायत परिवहन सुविधा शुरू कर सकती है। छोटी बसें या अन्य साधन पंचायत से तहसील और जिलों के लिए चलाए जाने चाहिए। यह काम पंचायतों को करना चाहिए। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी, पर सरकार ने इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया। निगरानी तंत्र फेल होने से यह नुकसान बसों

का किराया नियंत्रणविहीन है। निजी बस आपरेटर अपनी मर्जी से किराया बढ़ा लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद दोगुना से भी अधिक किराया बढ़ गया है। बस आपरेटर अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं। बस आपरेटरों की बीच प्रतिस्पर्धा के चलते भी वह नियमों की अनदेखी करते हैं। इसका बड़ा नुकसान यात्रियों को उठाना

पड़ता है। बिना परमिट और फिटनेस बसें चल रही हैं। निर्धारित क्षमता से तीन से चार गुना तक यात्रियों को बसें में भरा जाता है। इस कारण भी हादसे होते हैं। निगरानी नहीं होने से बसों में अवैध सामग्री के परिवहन भी होता है। कई ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं। विशेषज्ञ की राय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छोड़कर सभी राज्यों में लोक परिवहन की सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। मप्र में परिवहन माफिया की चल रही है। स्थानीय निकायों में सरकार निजी आपरेटरों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर बसों को संचालन करा रही है। निगरानी नहीं होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गुना में पिछले वर्ष बस में आग लगने के बाद सामने आया था कि उस बस का न तो परमिट था और न ही फिटनेस। जब घटना होती है तो कुछ दिन के लिए सरकार और तंत्र सजग होता है। इसके बाद सब भूल जाते हैं। लोक परिवहन की व्यवस्था सरकार दे तो लोगों को सस्ती और सुगम आवागमन सुविधा तो मिलेगी ही दुर्घटनाएं और बसों के जरिए होने वाला अवैध कारोबार भी रुकेगा। – श्याम सुंदर शर्मा, अध्यक्ष, यात्री सेवा परिषद मध्य प्रदेश

भोपाल। लोकसभा चुनाव की जंग चरम पर पहुंचने के साथ-साथ प्रदेश में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के दौरे भी बढ़ गए हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह सागर और हरदा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा शाम को भोपाल में पीएम मोदी भव्य रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पूर्व बुधवार सुबह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया और उनसे तीखे सवाल पूछा। जीतू ने कहा कि



शोमैन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिर से रोड शो करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन वे जनता के सवालों का जवाब दें और यह बताएं कि किसानों, युवाओं, महिलाओं को जो गारंटी दी थी, वह पूरी क्यों नहीं

कीं। भाजपा के नेता उन्हें बजरंगबली का अवतार भगवान और पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं तो यह भी बताएं कि बेरोजगारी क्यों है किसानों को उपज का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? जीतू ने यह

भी कहा कि मोदी गारंटी को लेकर चुनाव के बाद हम कोर्ट भी जाएंगे। **संवैधानिक संस्थाओं पर संकट तन्खा** राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए, ताकि वह संविधान बदल सके। आज सभी संवैधानिक संस्थाएं संकट में हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच सकता है जो इसे जुड़ा ना हो। पहले यह संभव नहीं था। 02 मई को मुरैना में प्रियंका का रोड शो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने यह जानकारी भी दी कि कांग्रेस महासचिव और पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड़ा 2 मई को मुरैना आएंगी। वहां पर प्रियंका रोड शो भी करेंगी।

वीडी शर्मा ने कहा- भ्रष्टाचार मुक्त भारत है मोदी सरकार का संकल्प, नेता हो या अधिकारी कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा

सिटी चीफ भोपाल।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन अन्य दिग्गजों की तरह अपने क्षेत्र में ही सीमित होने को तैयार नहीं दिखाई देते। खजुराहो में लगातार प्रचार और अधिक से अधिक मतदान कराने को अभियान भी चला रहे हैं, तो लगभग हर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में भी पहुंचते हैं। कई मौकों पर पार्टी के अन्य दिग्गजों के साथ मंच भी साझा करते हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद व्यस्त दिनचर्या में विष्णु दत्त शर्मा ने नईदुनिया से विशेष बातचीत की। ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों में राजनेताओं पर ही कार्रवाई कर रही है लेकिन नौकरशाह बच निकलते हैं, जबकि कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में चुनाव के लिए काला धन जुटाने पर



चुनाव आयोग ने भ्रष्ट अधिकारियों को भी शिकंजे में लेने की सिफारिश की है? इस सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से उचित बताते हुए कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया, मोदी सरकार में वह बच नहीं सका है। सभी भ्रष्टाचारियों पर तेजी से कार्रवाई हो

रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की गति और तेज होगी। उन्होंने जनधन खाते का उदाहरण देते हुए समझाया कि अब हितग्राहियों को सीधे बैंक खातों में पूरा पैसा मिलने से दलाल और बिचौलियों की बीच की कड़ी ही

खत्म हो चुकी है। डीबीटी पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत के प्रमुख अंश- मध्य प्रदेश में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाजपा राष्ट्रवाद का समुद्र है, इसमें वही गोता लगाएगा जिसमें राष्ट्रवाद के साथ देश की सेवा करने की ललक होगी। मोदी सरकार के कामों से प्रभावित होकर लोग भाजपा में आ रहे हैं। वह जानते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, तो मोदी के नेतृत्व में भाजपा में ही इसकी संभावना है। कांग्रेस छोड़कर आने वाले कहते हैं कि वहां घुटन होती थी, हमारे आराध्य श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा कर हमारे आराध्य का अपमान किया है। वहां हम खुलकर जय श्रीराम भी नहीं कह सकते थे।

अरेरा कालोनी में सुरक्षा गार्ड की सदमिध परिस्थितियों में मौत

भोपाल।अरेरा कालोनी स्थित ओल्ड कैम्पिन स्कूल के सुरक्षा गार्ड की सदमिध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह रविवार को रात्री में ड्यूटी पर पहुंचा था। सोमवार सुबह दूसरा गार्ड ड्यूटी पर पहुंचा तो नाइट गार्ड कमरे में मृत हालत में मिला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक कैलाश मगर (50) गणपति इन्वलेव कोलार रोड पर रहता था। रविवार की रात करीब सात बजे वह ड्यूटी पर पहुंचा था। सोमवार सुबह करीब सात बजे दूसरा गार्ड पहुंचा तो गार्डरूम भीतर से बंद मिला। गार्ड ने भीतर झांकिकर देखा तो कैलाश रूम के अंदर जमीन पर बेसुध हालत में पड़े दिखे। इसकी सूचना गार्ड ने उनके अवधपुरी में रहने वाले भाई को दी। कुछ देर में स्कूल का स्टॉफ भी पहुंच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रूम खुलवाया तो कैलाश की मौत हो चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि कैलाश को दो बार पहले भी अटक आ चुका था। पुलिस हार्ट अटैक से मौत होने का अनुमान लगा रही है, लेकिन सही कारणों का खुलासा पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो पाएगी।

भारत समेत एशिया में आपदा आने की रफ्तार कई गुना बढ़ी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक बीते साल एशिया में जलीय-मौसम संबंधी 79 आपदाएं आईं। इनमें 80 फीसदी आपदाएं बाढ़ और तूफान से जुड़ीं थी। इनके चलते बीते साल एशिया में दो हजार से ज्यादा लोगों की जान गई और 90 लाख लोग प्रभावित हुए। साल 2023 1991-2020 के औसत तापमान की तुलना में 0.91 डिग्री ज्यादा गर्म रहा।

जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ रहा है। इसी वजह से साल 2023 में एशिया दुनिया में सबसे ज्यादा आपदाओं से प्रभावित इलाका रहा। बाढ़ और चक्रवाती तूफान के चलते एशिया में बीते साल बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया की जलवायु-2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के पानी का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है, यहां तक कि आर्कटिक क्षेत्र में भी समुद्री गर्म हवाएं चल रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव केलेस्टे साउलो ने बताया कि एशिया के कई देशों में साल 2023 रिकॉर्ड स्तर पर गर्म रहा। इसके साथ बाढ़, सूखा, तूफान और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। जलवायु परिवर्तन से एशिया में आपदा आने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। जिसका असर हमारे समाज पर आर्थिक नुकसान, मानव जीवन के नुकसान और पर्यावरण पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते साल एशिया में जलीय-मौसम संबंधी 79 आपदाएं आईं। इनमें 80 फीसदी आपदाएं बाढ़ और तूफान से जुड़ीं थी। इनके चलते बीते साल एशिया में दो हजार से ज्यादा लोगों की जान गई और 90 लाख लोग प्रभावित हुए। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 1991-2020 के औसत तापमान की तुलना में 0.91 डिग्री ज्यादा गर्म रहा। वहीं 1961-1990 के औसत तापमान की तुलना में 1.87 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। जापान और कजाखस्तान में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी।

भारत में अप्रैल से जून के बीच भयंकर लू चली, जिसके चलते 110 लोगों की मौत हुई। अप्रैल से मई के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया लू से प्रभावित रहा, जिसका असर बांग्लादेश, पूर्वी भारत और चीन के उत्तरी और दक्षिणी इलाके शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तुरान तराई के इलाके (तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान), हिंदुकुश का इलाका (अफगानिस्तान, पाकिस्तान), हिमालय क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र का निचला इलाका (भारत, बांग्लादेश), अराकांस पर्वत (म्यांमार) और मेकाँग नदी के निचले इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई।

बीते साल दक्षिण पश्चिम चीन में सूखे, कम बारिश की समस्या देखी गई। भारत में मानसून के समय में भी कम बारिश हुई। जून, जुलाई और अगस्त में भारत, पाकिस्तान और नेपाल में कई जगहों पर बाढ़ और तूफान आए, जिनमें 600 से ज्यादा मौत दर्ज की गई। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं हुईं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि एशिया के पर्वतीय इलाकों में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे हिमालय और तिब्बत के पठार में बर्फ के ग्लेशियर सिमट रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। फिलीपींस और पूर्वी जापान के समुद्र का जलस्तर औसत से तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है।

पूरी दुनिया में अब जलवायु परिवर्तन का दर्श झेल रहे लोग, न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। हिंदुस्तानी भी इस दर्श से अछूते नहीं हैं बल्कि अगर देखा जाये तो पश्चिमी देशों के मुकाबले दक्षिणी एशियाई देशों पर जलवायु परिवर्तन के बुरे असरात कहर बनकर टूट रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पहली बार जलवायु परिवर्तन के बेरहम और जानलेवा दुष्प्रभावों से बचने के हक को जिंगरी के बुनियादी हक में तसलीम करके हिंदुस्तान के लाखों-करोड़ों गरीब और बेबस लोगों के जिंदा रहने के लिये ऑक्सीजन आने के दरवाजे खोल दिए हैं। यह जलवायु परिवर्तन से बचाव के अधिकार को एक बुनियादी हक के रूप में देखाता है। यानी साफ हवा में सांस लेना, साफ पानी पीने के लिए मिलना, नदियों का साफ बहाव, बेतहाशा गर्मी से बचाव, मौसम की मार से बचाव, ग्लेशियर तेजी से पिघलने की वजह को कम करना जैसी बातें अब हम आप हर हिंदुस्तानी के जीने के हक में शामिल है। खासतौर से ऐसे हालात में जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देश भीषण सूखे, प्रलयकारी बाढ़ और भयंकर तपिश के दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं।

मुइज्जू और मालदीव की मुश्किलों के बीच नहीं होगा भारत की नीतियों में बदलाव

बीते 21 मई को मालदीव में संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के गठबंधन पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने भारी जीत हासिल की, जिसने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के साथ गठबंधन किया था। आरोप हैं कि चीनी पैसे के बल पर नतीजे बदल दिए गए। मालदीव की संसद में कुल 93 सीटें हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या कहीं 1,000 से भी कम है, तो कहीं 3,000 से थोड़ा ज्यादा। निवर्तमान पीपुल्स मजलिस ने मुइज्जू की कई पहलों के साथ-साथ नामांकित केबिनेट सदस्यों की नियुक्ति को भी रोक दिया था। अब कम से कम कुछ महीनों तक राष्ट्रपति समर्थक और विरोधी सांसदों को मारपीट करते हुए नहीं देखा जा सकता है। वर्ष 2023 में मुइज्जू इंडिया आउट अभियान चलकर राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया और उनके कुछ भारतीय पिछलग्गू इसे चीन की बहुत बड़ी जीत और भारत का भारी नुकसान बता रहे हैं, खासकर भारतीय सेना की छोटी-सी टुकड़ी के मालदीव छोड़ने के बाद। लेकिन ये विश्लेषक भ्रमित हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध खास खेल नहीं, ब्रिजमें एक पक्ष को जिताना लाभ होता है, ठीक उतनी ही हानि दूसरे पक्ष को होती है। यह बार-बार साबित हो चुका है, लेकिन कुछ लोग इससे सोखना नहीं चाहते। श्रीलंका में बेहद भ्रष्ट गौटबाया राजपक्ष परिवार (जो चीन का वफादार सेवक था) का शासन 2022 के मध्य में ताश के पत्तों की तरह ढल गया। वह कोलंबो से भागकर मालदीव गए, लेकिन वहां से भी उन्हें जाने के लिए कहा गया, तो सिंगपुर गए। उन्हें चीनी आका ने छोड़ दिया। या म्यांमार का ही उदाहरण ले लीजिए। बीजिंग समर्थित सैन्य शासन लड़खड़ा रहा है, विश्वी गठबंधन का

देश के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण है। म्यांमार में दो शब्द सर्वाधिक घृणित हैं-चीन और सेना।क्या मालदीव, जो 90,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैले 26 प्रवाल द्वीपों के आसपास करीब 1,200 मूंगा द्वीपों से बना है, अपने भविष्य पर ध्यान देगा? यदि ग्लोबल वार्मिंग मौजूदा गति से ही जारी रही, तो मालदीव अगले एक दशक में गायब हो जाएगा। फिर क्या वहां के लोग चीन जाएंगे?मालदीव के आयात शुल्क संग्रह में भारी गिरावट आई है, क्योंकि उसका चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। मार्च, 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को अपना करीबी सहयोगी बताते हुए ब्रह्म राहत की गुहार लगाई, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पर्यटकों की संख्या भी 30 फीसदी कम हो गई है। बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा मालदीव का दौरा रद्द करने से उसके पर्यटन उद्योग में भूचाल आ गया है और आतंकवादियों से भी उसके रिश्ते उजागर हो गए हैं। फिर भी अप्रैल 2024 में, भारत से आवश्यक खाद्य पदार्थों की मांग के बाद, जिनमें कुछ ऐसे सामान भी थे, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध है, हमने वे चीजें भेजकर दयालुता दिखाई, जबकि चीन ने केवल पीने का पानी भेजा था। मालदीव के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि वह भारत की उदारता के लिए दिल से आभारी हैं। भारत ने 1980 के दशक में तख्तापलट के प्रयास को विफल करने में मालदीव की सहायता की और 2000 के दशक में जब वहां पानी का घोर संकट था, तो पेयजल की आपूर्ति की थी। फेलिक्स श्वार्जेंनबर्ग ने हमें 19वीं सदी के मध्य में बताया था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में कृतज्ञता जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह बात हम जानते हैं।

अभिप्राय/संस्था

मतदाता के मानस को प्रभावित करने का टोटका?

वया चुनाव में केवल अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखाने का दुस्साहस है अथवा मतदाता के राजनीतिक रुझान और मनोविज्ञान को पहले ही मांप लेने की जादूगरी है? या फिर चुनाव के बाजार में अपने ब्रांड का भाव ऊंचा कायम रखने का टोटका है?

आजकल चुनाव में मतदान के आरंभिक चरण के आधार पर ही संभावित अंतिम नतीजों की अटकलें लगाने का काम जोरों पर है। इस बार भी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में घटे मतदान की बिना पर दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों ने अपनी- अपनी जीत के दावे ठोक दिए हैं। गोया कि मतदाता उनकी हार-जीत पहले ही चरण में सुनिश्चित कर दी हो। जब चुनाव के 6 चरण बाकी हों, तब ऐसे दावों का क्या मतलब है? क्या चुनाव में केवल अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखाने का दुस्साहस है अथवा मतदाता के राजनीतिक रुझान और मनोविज्ञान को पहले ही भांप लेने की जादूगरी है? या फिर चुनाव के बाजार में अपने ब्रांड का भाव ऊंचा कायम रखने का टोटका है? इन सवालों को बल हाल में सोशल मीडिया पर आई दो पोस्ट से मिला, जिनमें से पहले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की तुलना में कम मतदान के आंकड़े सामने आने के बावजूद कहा कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान के लिए मतदाताओं का धन्यवाद तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट डाली कि (चुनाव में) भाजपा का पहले दिन का शो फ्लॉप। मतदाताओं की नई राजनीतिक चेतना को नमन। दरअसल, पहली पोस्ट का आशय साफ था कि देश में मोदी लहर पहले की तरह उड़ाम गति से बह रही है, कोई इसे न समझना चाहे तो न समझे। दूसरी पोस्ट का मतव्य था कि जो वोटिंग हुआ है, वह मुख्यत् तन वोटरों द्वारा किया गया है, जो भाजपा और एनडीए के विरोधी हैं यानी कि इंडिया गठबंधन को सत्ता में आते देखना चाहते हैं। यानी कि अखिलेश ने मान लिया है कि चुनाव के बाकी चरणों में भी मतदान का वही ट्रेंड रहने वाला है, जो पहले चरण में दिखा। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी राज जा रहा है, नेताविहीन इंडिया गठबंधन सामूहिक राज आ रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहले ही से मान बैठे हैं कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ तो महज संवैधानिक औपचारिकता है, जनता उनके स्वस्तिवाचन के लिए उधार बैठी है। चुनाव का लोकतांत्रिक सच इन दोनों के भीतर कहीं है। यह सही है कि 2019 के मुकाबले इस बार पहले चरण का मतदान तुलनात्मक रूप से कम दर्ज किया गया है। पिछले लोस चुनाव भी



सাত चरणों में हुए थे, तब पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसका प्रतिशत 66 था। इस बार 21 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट पड़े, जिसका प्रतिशत 65.5 फीसदी था। यानी 0.5 फीसदी का फर्क। हालांकि जिन सीटों पर वोट पड़े, वो वही नहीं थीं, जो 2019 में थीं। इसलिए मतदान के प्रतिशत की सीटवार तुलना उचित नहीं होगी। बहरहाल, मतदान प्रतिशत में मामूली कमी से अंतिम नतीजों पर बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। यही ट्रेंड आगे भी दिखे, यह जरूरी नहीं है। फिर भी पहले चरण को मंगलाचरण मानकर अर्चना का फलित तलाशने वाले नतीजों की एडवांस घोषणा क्यों कर रहे हैं? सत्ता के घोड़े की सवारी को लेकर इतना उतावलापान क्यों है? क्या यह महज राजनीतिक सनसनी फैलाने का शिगूफा है अथवा मतदाता के मानस को प्रभावित करने का सियासी टोटका है? इसे हमे समझना पड़ेगा। दरअसल मतदान के पहले चरण के झटके से दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमे हिले हुए क्यों हैं, इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। मतदान खासतौर पर उन राज्यों में घटा है, जहां भाजपा और एनडीए ज्यादा से ज्यादा और बड़ी संख्या में सीटें जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं। जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन की सेनाएं सीधे आमने सामने हैं, उस बिहार में महज 47.49 फीसदी वोट पड़े हैं। मतदान का यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 10 फीसदी कम है। पिछले चुनाव में जदयू- भाजपा व अन्य कुछ छोटी पार्टियों के गठबंधन ने बिहार में स्वीप करते हुए 40 में से 39 सीटें जीत ली थीं, केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब मतदान में भारी कमी का नुकसान किसे होगा, इसको लेकर राजनीतिक अटकलबाजी जारी है। इधर, कुछ जानकारों का मानना है कि जदयू का एनडीए में लौटना खास मुफीद साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीशा की राजनीतिक साख पर लगा बट्टे की वाशिंग उस तरह से नहीं हो पाई, जो अपेक्षित

सियासत-घटता-बढ़ता रहता है मतदान, इसे ट्रेंड न माना जाए

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने को लेकर कई तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। पहले चरण में नौ राज्यों तथा तीन केन्द्रशासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है। माना जा रहा था कि देश के एक बड़े हिस्से में मतदान संपन्न होने के बाद इसकी प्रवृत्तियों का आकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मतदान के बाद आम टिप्पणी यही है कि मतदान प्रवृत्तियों का आकलन आसान होने के बजाय कठिन हुआ है।

बहरहाल, पहले चरण के मतदान की सबसे बड़ी विशेषता रही कि पश्चिम बंगाल और मणिपुर को छोड़कर कहीं भी हिंसा की घटना नहीं हुई। किसी बड़ी घटना का न होना बताता है कि हमारे देश का चुनाव तंत्र बिल्कुल सहज, सामान्य और सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि हम कम अवधि और कम चरणों में भी लोकसभा चुनाव को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर हो रही है और इस बारे में कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों में मतदान की प्रतिशत ज्यादा गिरा है। इनमें भी सभी जगह मतदान एक समान भी नहीं रहे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ज्यादा मतदान हुए, तो



बिहार और उत्तराखंड में अत्यंत कम। इन दोनों राज्यों में भी अलग-अलग क्षेत्र को देखें, तो कहीं ज्यादा, तो कहीं कम मतदान हुआ है। यह साफ है कि एकाध स्थानों को छोड़कर ज्यादातर जगहों में मतदान प्रतिशत गिरा है। उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले लगभग 5.30 प्रतिशत कम मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, यह करीब 68.29 प्रतिशत है। यानी करीब 1.14 फीसदी कम मतदान हुआ है, तो कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत में ज्यादा गिरावट नहीं है। नगालैंड में मतदान प्रतिशत इसलिए ज्यादा गिरा, क्योंकि वहां के छह जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया।

ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स फ्रंट ने अलग राज्य की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। इसे हम मतदान में कमी की प्रवृति नहीं मान सकते। करीब डेढ़ दशक पहले मतदान घटने का अर्थ सत्तारूढ़ घटक की विजय तथा मतदान बढ़ने का अर्थ पराजय के रूप में लिया जाता था और प्रायः ऐसा देखा भी गया। किंतु 2010 के बाद यह प्रवृति बदली है। मतदान बढ़ने के बावजूद सरकारें वापस सत्ता में आई हैं और मतदान घटने के बावजूद गई भी हैं। इसलिए इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरे, हर जगह मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा भी नहीं है। तीसरे, बंगाल में साफ दिखाई दे

रहा है कि दोनों पक्षों के मतदाताओं में एक-दूसरे को हराने और जिताने के लिए प्रखर प्रतिस्पर्धा है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत का घटना सामान्य नहीं है। इस क्षेत्र में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में यह आकलन करना कठिन है कि जहां मतदान प्रतिशत गिरा, वहां किस पक्ष या पार्टी के मतदाता नहीं आए। अगर भाजपा विरोधी उसे हराना चाहते थे, तो उन्हें भारी संख्या में निकलना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि सपा के कोर मतदाता यानी मुसलमान और यादवों का बड़ा समूह आक्रामक होकर मतदान कर रहा था। विरोधी भारी संख्या में

निकलेंगे, तो समर्थक भी इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि उम्मीदवारों के चयन, दूसरे दलों से आए लोगों को महत्व मिलने तथा कहीं-कहीं गठबंधन को लेकर भाजपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष है तथा एक जाति विशेष ने भी विरोधात्मक रूप अस्तित्‍वार किया था। बावजूद इसके यह कहना कठिन होगा कि भाजपा समर्थक मतदाता ही ज्यादा संख्या में मतदान करने नहीं निकले। अभी तक के चुनाव अभियान में जनता की उदासीनता दिखी है। हालांकि विपक्ष के प्रचार के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर आम जनता में व्यापक आक्रोश नहीं दिखा है। कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थी तथा विकास नीति की प्रशंसा करने वाले हर जगह दिखाई देते हैं। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से लेकर समान नागरिक संहिता एवं नागरिकता संशोधन कानून आदि पर विपक्ष के रवैये ने भाजपा समर्थकों में प्रतिक्रिया भी पैदा की है। असंतुष्ट लोगों में भी यह भाव है कि अगर यह सरकार हार गई, तो कहा जाएगा कि हिंदुत्व विचारधारा की हार हो गई है। जिस जाति के विद्रोह की चर्चा हो रही है, वे भी भाजपा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने भाजपा के विरोध में मतदान किया होगा।



से गुंजायमान हो गया।



मध्य प्रदेश में ए प्लस ग्रेड में शाजापुर जिले को मिला उत्कृष्ट स्थान

बच्चों ने रचा इतिहास

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ शाजापुर, परीक्षा के बाद अपने परिणामों की राह देख रहे विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिसकी शुरुआत मंगलवार को कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट से हो गई। जिसमें इस बार जिले के विद्यार्थियों ने इतिहास रचते हुए प्रदेश में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। इस बार शाजापुर जिला ए प्लस ग्रेड के मामले में कक्षा 5वीं में 18वे तथा कक्षा 5वीं में 16वे स्थान पर रहा। इस बार जिले से कक्षा 5वीं में 15019 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 13 हजार 353 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 4 हजार 957 विद्यार्थियों को ए ग्रेड प्राप्त हुई है। इस प्रकार कक्षा 5वीं में 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली। जबकि कक्षा 8वीं में 15 हजार 198 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 13 हजार 353 विद्यार्थियों को सफलता मिली है। इनमें से 4 हजार 957 विद्यार्थी ए प्लस ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हुए हैं



और कक्षा 5वीं में 3 हजार 930 विद्यार्थियों को ए प्लस ग्रेड मिली है। इस प्रकार जिला प्रदेश में ए प्लस ग्रेड में 18वां तथा 8वीं में ए प्लस ग्रेड के मामले में प्रदेश में जिले को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह शाजापुर जिले ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में कई जिलों को पीछे छोड़ दिया है।

परिणाम के मामले में पिछड़ा जिला-इस बार ए प्लस ग्रेड से पास होने वाले विद्यार्थियों ने जिले को पहचान दिलाई है। लेकिन यदि

बात परिणामों की की जाए तो कक्षा 5वीं में जिला 40वे स्थान पर तथा 8वीं में 37वे स्थान पर आया है। जिसमें अभी भी सुधार की जरूरत है। जिला शिक्षा केंद्र के अनुसार जिले के किन स्कूलों में परिणाम कम आए हैं और जहां ज्यादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिलेंगे अवसर-जिला शिक्षा केंद्र

के डीपीसी राजेंद्र शिरे ने बताया कि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें मौके दिए जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसे दो मौके दिए जाएंगे और कोई एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसे एक मौका और दिया जाएगा। इसके लिए अभी स्पष्ट आदेश नहीं आए हैं। आगामी दिनों में जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि इसके बाद भी वे सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें पूरी तरह फेल माना जाएगा।

खराब परिणामों की भी होगी समीक्षा- डीपीसी शिरे ने बताया कि ऐसे विद्यालय जिनके यहां परीक्षा परिणाम खराब रहा है और ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ है। इसकी भी जांच की जा रही है। इसके बाद इन परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी। एक दो दिन में ऐसे विद्यालयों की भी सूची प्राप्त हो जाएगी।

मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ऋषु बाफना ने करा निर्बंधित

शाजापुर में 06 व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए किया निर्बंधित

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ऋषु बाफना द्वारा जिले के 06 व्यक्तियों को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली शाजापुर मुगलपुरा निवासी 19 वर्षीय नदीम खान उर्फ गुडा पिता अजीज खान, थाना शुजालपुर सिटी ग्राम दुग्धा निवासी 30 वर्षीय एलम पिता पीरुलाल सूर्यवंशी, थाना अकोदिया ग्राम फुलेन निवासी 33 वर्षीय मिथुन उर्फ कालू पिता केशरसिंह मेवाड़ा, ग्राम सलसलाई निवासी 34 वर्षीय अंतरसिंह पिता सुभाष सिंह मेवाड़ा, मकसी थाना बावड़ी मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय अनीस खान पिता मजीद खान तथा थाना सुनेरा ग्राम पनवाड़ी निवासी 48 वर्षीय साबिर पिता रशीद खॉं को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है। निर्बंधन आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने



सभी को आदेश दिये हैं कि वे आदेश प्राप्ति से 01 वर्ष की कालावधि तक प्रत्येक माह में संबंधित तहसीलदार के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः देंगे तथा 01 वर्ष की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे आवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वह अपने निवास ग्राम/शहर से अन्यत्र प्रस्थान करता है संबंधित एसडीएम/थाना प्रभारी/तहसीलदार को समक्ष में उपस्थित होकर देगा एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की

धारा 3 (1) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्बंधित किया है कि, अनावेदक किसी भी व्यक्ति के शरीर व सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेंगे व उपयोग में नहीं लायेंगे। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी है कि वह अपने आप को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखेंगे एवं आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाये रखेंगे

रामदुलारे के दर्शन को उमड़ पड़े राम भक्त

जिले भर में धूमधाम से मनाया हनुमान प्रकटोत्सव



भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, बेगि हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारी, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा, इन भजनों के साथ मंगलवार के दिन की शुरुआत हुई और दिनभर शहरवासी रामभक्त हनुमान के जन्मोत्सव में व्यस्त रहे। कहीं भंडारे का आयोजन किया

गया तो कहीं पर अभिषेक और प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ, जिसका हजारों शहरवासियों ने लिया। राम भक्त हनुमान को कई जगह छप्पन भोग लगाया गया तो कई जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया।

जिलेभर में रामदूत के पवनपुत्र के जन्मोत्सव का उत्साह देखते ही



बन रहा था। जिले के हनुमान मंदिरों में मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। कहीं अखंड रामायण की पूर्णाहुति हुई, तो कहीं संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सुबह से लेकर रात तक हनुमानजी के भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन किए। नगर के प्रसिद्ध डॉसी हनुमान मंदिर में अलसुबह से ही बाबा का अभिषेक किया जाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। अतिप्राचीन मुरादपुरा हनुमान मंदिर में भी सुबह ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। दिनभर बाबा के दर्शन का सिलसिला चलता रहा। शाम होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ गई, जो देर रात तक चलती रही। बाबा की महाआरती में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बालवीर हनुमान मंदिर पर भी कई दिनों से चल रही तैयारियों ने आयोजन को चार चांद लगा दिए तो बाबा बालवीर के श्रृंगारित स्वरूप को निहारने के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की कतार लगी रही। यहां भी प्रभु को श्रीखंड का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। रात 8 बजे हुई बाबा बालवीर की महाआरती में भक्तों का सैलाब

उमड़ा। यहां भी लगी भक्तों की कतार- शहर के श्री शनिविजय हनुमान मंदिर, लालपुरा स्थित हनुमान मंदिर, विजयश्री हनुमान मंदिर हरायपुरा, हनुमान मंदिर वजीरपुरा, काशी विश्वनाथ महादेव स्थित हनुमान मंदिर विजयनगर, गिरवर हनुमान मंदिर, मूलीखेड़ा रोड स्थित हनुमान मंदिर, बलवीर हनुमान मंदिर भावसार मोहल्ला सहित नगर के 100 से अधिक छोटे-बड़े हनुमान मंदिरों में बाबा की जयंती धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई गई।

सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर उमड़ी भीड़- जिले के चमत्कारी श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां सुबह बाबा का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा को छप्पन भोग लगाया गया। इसके पूर्व बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया था जिसे निहारने कोलार्ड सहित जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी यहां पहुंचे और सिद्धवीर बाबा का आशीर्वाद लिया। यहां सुबह से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। जिसके चलते मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहां प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया।

डीएम डा. दिनेश चंद्र ने फीता काटकर व आसमान में गुब्बारे और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर किया भव्य उद्घाटन देवबंद के प्रसिद्ध मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी शक्तिपीठ के देवीकुंड मैदान पर लगने वाले वार्षिक मेले का हुआ आयोजन



गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद, सहारनपुर, देवबंद के प्रसिद्ध मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी देवी शक्तिपीठ के देवीकुंड मैदान पर नगर पालिका परिषद देवबंद के तत्वावधान में हर वर्ष लगने वाले वार्षिक मेले का जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र ने फीता काटकर व आसमान में गुब्बारे और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मेला आज से आरंभ हो गया है। आज माता के भवन पर प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र कालिका प्रसाद ने मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा संपन्न कराई। मेला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अधिकारियों से धार्मिक मेले की गरिमा बनाए रखने व बिजली, सफाई तथा पेयजल जैसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी

डा.दिनेश चन्द्र सिंह ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मेलों से सांप्रदायिक सौहार्द को बल मिलता है। इससे पूर्व डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मां बाला सुंदरी देवी मंदिर जाकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष ने विधि-विधान के साथ पूजा संपन्न कराई। मेला पंडाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग व अधिशासी अधिकारी डा. धीरेंद्र कुमार राय ने कहा कि मेले को उसकी गरिमा के अनुरूप भरवाया गया है। मेले व मंदिर में आने वाले लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धीरेंद्र कुमार राय, पालिकाध्यक्ष विपिन गर्ग, मेला

चेयरमैन व सभासद अंकित राणा, सीओ देवबंद अशोक सिसौदिया, देवबंद कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार, पं. कालिका प्रसाद, जिला कोपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौ. राजपाल सिंह, सभासद सैयद हारिस, चौ. ओमपाल सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी अशोक गुप्ता, अजय गांधी, लक्की वर्मा, बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी, विजय त्यागी, देवीदयाल शर्मा एडवोकेट, रितेश बंसल, चौधरी प्रविंद्र, हाजी शहजाद, पूर्व सभासद विनय कुच्छल काका, जावेद खान, वसीम मलिक, रिजवान गौड़, शराफत मलिक, आसिफ लियाकत समेत भारी संख्या में श्रद्धालु व समाजसेवी लोग मौजूद रहे।

इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ सहित दीनी इदारों में नवीन सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाएं हुई आरंभ संस्थाओं में एडमिशन प्राप्त करने की ख्वाहिश लेकर देश के अलग-अलग प्रांतों से हजारों छात्र यहां पहुंचे



गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद। सहारनपुर, इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ सहित दीनी इदारों में नवीन सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। इन संस्थाओं में एडमिशन प्राप्त करने की इच्छा लेकर देश के अलग-अलग प्रांतों से हजारों छात्र यहां पहुंचे हैं। प्रवेश के लिए लिखित परीक्षाएं कराई गईं। जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम व दारुल उलूम वक्फ सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए फार्म भरे गए थे। दारुल उलूम और दारुल उलूम वक्फ में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षाएं कराई गईं। इन परीक्षाओं में बैठने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से करीब 15 हजार छात्र आए हुए हैं। इसमें 10 हजार छात्रों ने दारुल उलूम और शेष ने दारुल उलूम वक्फ सहित अन्य दीनी इदारों में फार्म भरे हुए थे। दारुल उलूम प्रबंधन का कहना है कि 30 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर 1 मई से वर्ष 2024-2025 के लिए नए सत्र का आगाज कर दिया जाएगा। दारुल उलूम के नायब मोहतामिम शकेब कासमी ने बताया कि पांचवी कक्षा के नतीजे आ चुके हैं। शेष कक्षाओं के लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नवीन सत्र का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दारुल उलूम जकरिया, जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह, जामिया तुश शेख हुसैन अहमद अल मदनी, दारुल उलूम अशराफिया सहित अन्य दीनी इदारों में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।

यूपी के आठ सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए सुस्त मतदान ने बढ़ाई भाजपा की चिंता

अंदरूनी स्तर पर मंथन शुरू

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, 2019 के मुकाबले अबकी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आठ सीटों पर छह फीसद कम वोट पड़ने से सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा चिंता भाजपा के चुनाव प्रबंधकों में सामने आ रही है। भाजपा के रणनीतिकार राजपूतों की नाराजगी को भी एक वजह मान रहे हैं लेकिन मंथन में जो तीन प्रमुख बिंदु उभरकर सामने आए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भाजपा का कार्यकर्त्ता मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आखिर क्यों नहीं ले जा पाया। इस बार भाजपा के रणनीतिकार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की अपनी पहली मेरठ और दूसरी सहारनपुर की चुनावी सभाओं में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बहुत जोर दिया था। लेकिन पहले चरण के चुनाव में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, रामपुर मनिहारान, मुरादाबाद और पीलीभीत पर 2019 के

चुनाव में सभी जगह करीब छह फीसद कम वोट पड़े। 2014 और 2019 के चुनावों के विपरीत अबकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाता ना तो हिंदुत्व और ना ही राष्ट्रवाद की लहर पर सवार था। जिसकी भरपूर कोशिश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। जातीय गोलबंदी ने भाजपा के प्रबंधकों को उलझा दिया। आखिरी वक्त तक भाजपा के रणनीतिकार जातिवाद की काट नहीं कर सके। यह सवाल सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा कर रहा है कि लोकसभा के पिछले दो चुनावों और उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों चुनावों में कार्यकर्त्ताओं में जो जोश दिखता था वह पहले चरण में क्यों सिर से गायब रहा। पुलिस और प्रशासन का रवैया भी पिछले सभी चुनावों से बिल्कुल अलग था। इस बदलाव ने भाजपा को हैरान कर दिया। पहले नंबर की सीट सहारनपुर पर अबकी 66.65 फीसद वोट पड़े और 2019 में इसी सीट पर

70.87 फीसद वोट पड़े थे। कैराना सीट पर 61.17 फीसद वोट पड़े पिछले चुनावों में 67.45 फीसद वोट पड़े थे। मुजफ्फरनगर सीट पर जहां भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान हैं वहां केवल 60.02 फीसद वोट पड़े जबकि 2019 के चुनावों में वहां 68.42 फीसद मतदान हुआ था। 8 फीसद की गिरावट भाजपा खेमे में बैचेनी पैदा किए हुए है। संजीव बालियान पिछले चुनाव में किसी तरह से अजीत सिंह को हरा ने में सफल हो गए थे जबकि इस बार अजीत सिंह से बहुत हल्के हरेन्द्र मलिक के सामने उनके पसीने छूट गए। बिजनौर सीट पर भी मतदान में 8 फीसद की बड़ी गिरावट रही। इस सीट पर भाजपा के समर्थन से रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान मैदान में रहे जिन्हें सपा-बसपा उम्मीदवारों के बीच मतों के बंटवारे का लाभ मिलता दिखा। शायद उसी आधार पर चंदन चौहान अन्य सीटों की उम्मीदवारों की अपेक्षा जीत के प्रति आश्वस्त हैं। रामपुर सीट पर अबकी 55.75 फीसद ही वोट पड़ पाए जबकि 2019 में

63.19 फीसद वोट पड़े थे। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद सीट पर भी मतदान 5 फीसद गिरा। मुरादाबाद में 60.05 फीसद वोट पड़े। पिछले चुनाव में 65.46 फीसद वोट पड़े थे। इस बार और पिछले बार के चुनावों में बड़ा बदलाव यह था कि कांग्रेस-सपा-बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में बेहद सतर्कता बरती। कैराना सीट पर सपा-कांग्रेस उम्मीदवार इकरा हसन अकेली मुस्लिम उम्मीदवार थी। वहां मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने वाला कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। बसपा ने यहां जानबूझकर और राजपूतों की नाराजगी का फायदा उठाने की गरज से राजपूत श्रीपाल सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया था। मुजफ्फरनगर सीट पर किसी भी प्रमुख दल का उम्मीदवार मैदान में नहीं था। सपा के कांग्रेस समर्थित जाट उम्मीदवार हरेन्द्र मलिक को चार लाख मुस्लिम मतों का बड़ा सहारा मिला। बिजनौर सीट पर भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं था। यह अलग बात है कि वहां गैर भाजपाई मतों के



बीच सपा और बसपा में बंटवारा हो गया। मुरादाबाद सीट पर भी अखिलेश यादव ने सोच समझकर अपने मुस्लिम सांसद डा. एसटी हसन के बजाए बनिया बिरादरी की रूचि बीरा को उम्मीदवार बनाया। वहां भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हो पाया। हालांकि बसपा ने वहां जरूर मुस्लिम सैफी बिरादरी का उम्मीदवार खड़ा किया था। इस तरह से पहले चरण के मतदान को लेकर भाजपा के बजाए विपक्षी खेमा यानि ईंडिया गटबन्धन अपनी जीत के दावे कर रहा है। भाजपा अभी मजबूती के साथ जीत का दावा करने के लिए सामने नहीं आ पाई है। भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि भाजपा

कार्यकर्त्ताओं में मायूसी की एक वजह यह भी सामने आई है कि मतदान के पहले दिन तक विपक्षी दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता रहा। उससे चुनाव में फायदा तो नहीं हुआ लेकिन कार्यकर्त्ताओं में निराशा जरूर घर कर गई। भाजपा के चुनाव रणनीतिकारों की बात माने तो भाजपा आलाकमान अगले चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और पार्टी नेतृत्व बदली हुई रणनीति पर काम कर रहा है। राजनीतिक समीक्षकों की निगाहें अब अगले चरण के मतदान पर टिक गई हैं। उसके रूझान से देश के चुनावी माहौल का थोड़ा-बहुत अंदाजा हो जाएगा।

उप्र, सहारनपुर में कार अनियंत्रित होकर फतेहपुर-कलसिया मार्ग पर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराई

हादसे में आठ साल के बच्चे सहित चार लोगों की हुई मौत, किशोरी समेत दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, सहारनपुर जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत महेश्वरी गांव में वलीमे की दावत खाकर लौट रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर फतेहपुर-कलसिया मार्ग पर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। इसमें आठ साल के बच्चे सहित चार लोगों की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि 16 साल की किशोरी सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मरने वाले और घायल आपस में रिश्तेदार हैं। घायलों को फतेहपुर सीएचसी से जिला अस्पताल भेजा गया है। चार मौतों से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने के गांव अमानतगढ़ निवासी बिलाल पुत्र अफजाला की बहन आईशा की शादी कोतवाली देहात के गांव महेश्वरी में हुई थी। वलीमे की दावत में बिलाल अपने रिश्तेदारों के साथ गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त उनकी कार बेकाबू



होकर फतेहपुर कलसिया मार्ग पर गांव मांडुवाला के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बिलाल के बहनोई नईम (26) पुत्र जमशेद निवासी गढ़मपुर

हरिद्वार, नईम का बेटा आशु (7), चचेरा भाई अरहान (18) पुत्र जीशान निवासी अमानतगढ़ और दूसरा बहनोई आरिफ (34) पुत्र जहूर हसन निवासी गांव ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिलाल और

उनकी भांजी आलिया (15) पुत्री आरिफ निवासी अमानतगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने फतेहपुर सीएचसी भर्ती कराया। जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया।



गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, सहारनपुर जनपद के थाना मिर्जापुर निवासी हाफिज महफूज के बेटे डॉ. अब्दुल्लाह की 7 मई को बारात जानी थी।अब्दुल्लाह अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहे था कि रास्ते में सड़क हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिससे उसकी शादी की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर निवासी डॉ. अब्दुल्लाह अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहा था सहारनपुर जाते समय विकासनगर हाइवे पर गांव

कलसिया के पास सामने से आ रहे बाईक सवार एक युवक ने जबरदस्त कट मारा जिससे उसकी बाइक टकरा गई। मृतक का सिर सड़क में लगने से उसकी मौके पर

ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गई।

दिल्ली यमुनौत्री हाइवे पर ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर टक्कर लगने के बाद लगी बाइक में आग, बाइक चालक की हुई मौत



गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, दिल्ली यमनौत्री नेशनल हाइवे पर ग्राम जन्हेड़ा समसपुर के पास तेज गति से दौड़ रही एक ट्रैक्टर-ट्राली ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाईक सवार रामपुर निवासी सुमित की ट्राली में फंसकर गर्दन कट गई। जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाईक भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर बिगड़ की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू गया।

भगवान महाकाल के शीश पर बंधी गलंतिका गर्मी से बचाने के लिए शीतल जलधारा प्रवाहित

उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर गलंतिका बांधी गई। मिट्टी से निर्मित मटकियों से भगवान के शीश पर सतत शीतल जलधारा प्रवाहित की जा रही है। ज्योतिर्लिंग की परंपरा अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक दो माह प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी जाती है। इसके पश्चात विष की उष्णता शांत करने के लिए भगवान शिव का निरंतर जलाभिषेक किया जाता है। गर्मी के दिनों में विष की उष्णता बढ़ जाती है। इस कारण वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलशों से शीतल जलधारा प्रवाहित की जाती है। इन कलशों को गलंतिका कहा जाता है। महाकाल मंदिर में बुधवार को वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर भगवान महाकाल को गलंतिका बांधी गई। यह गलंतिका ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक रहेगी। गलंतिका स्वरूप बंधे कलशों में प्रतीकात्मक स्वरूप में विभिन्न नदियों के नाम अंकित किए जाएंगे। ये नदियां हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरयू, शिप्रा, गंडक आदि। यह जलधारा प्रतिदिन भस्मरती पश्चात शुरू होकर सायं पूजन तक जारी रहेगी। प्रतिवर्ष मंदिर में वैशाख और ज्येष्ठ माह में अभिषेक पात्र (रजत कलश) के साथ मिट्टी के 11 कलशों के साथ गलंतिका बांधी जाती है।



लोकसभा चुनाव से पहले किराएदार हो रहे चिन्हित, पुलिस घर-घर जाकर कर रही सर्वे

भिंड। लोकसभा चुनाव में 14 दिन बाकी हैं। जिले में करीब 35 हजार किराएदार हैं। पुलिस के पास किराएदारों की सूची अपडेट नहीं है। ऐसे में ये किराएदार चुनाव के दिन मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। एसपी डा. अमित यादव ने शहर सहित अंचल में रहने वाले किराएदारों की सूची तैयार करवा रहे हैं। ताकि पुलिस को यह पता रहे कि किस घर में कौन किराएदार रह रहा है।एसपी यादव के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बाहरी लोग किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकें, इसलिए शहर सहित अंचल में रहने वाले किरायेदारों की सूची तैयार करवा रहे हैं। जिले में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह बीट प्रभारी के माध्यम से किराएदारों की सूची तैयार कराएं और उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखें।



सकते हैं, क्योंकि उप्र सहित अन्य प्रदेशों के असामाजिक तत्व भी किराएदार के रूप में रह सकते हैं और चुनाव को प्रभावित कर निकल सकते हैं। **लापरवाही पर तीन साल की सजा-** एसपी के मुताबिक लापरवाही पर किसी भी मकान मालिक को 3 साल सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिला

प्रशासन धारा 144 के तहत किराएदारों की जानकारी पुलिस को देने का आदेश जारी करता है। यह आदेश एक निर्धारित समय सीमा के लिए होता है। इसका उल्लंघन होने पर भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। **ऐसे दें किराएदारों की जानकारी-** एसपी के मुताबिक

मकान या दुकान में नया किराएदार नौकर रखते समय आपको उसकी संपूर्ण जानकारी एक आवेदन बनाकर थाने में जमा करानी होती है। इसमें उसका नाम, पता, स्थायी पता, नौकरी और फोटो समेत उसके स्थाई पते के दो पड़ोसियों के फोन नंबर देने होते हैं। कुछ थानों में बाकायदा इसका फार्म भी भरवाया जाता है।

‘प्रचंड बहुमत के बाद बोले मुइजू-चुनाव नतीजों से साफ हुआ मालदीव के लोग क्या चाहते

माले मालदीव के संसदीय चुनाव में ‘प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब पता चल गया होगा कि विशेष रूप से ‘‘संप्रभुता और स्वतंत्रता के मुद्दे पर इस देश के लोग क्या चाहते हैं। चीन समर्थक मुइजू का यह बयान चुनावी जीत से जुड़े एक समारोह के दौरान सोमवार को आया था। उनके नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने रविवार को हुए चुनाव में 93 में से 68 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उसके गठबंधन सहयोगियों मालदीव नेशनल पार्टी (एमएनपी) ने एक और मालदीव डेवलपमेंट अलायंस (एमडीए) ने दो सीट जीतीं। इस तरह पीएनसी और उसके सहयोगी दलों को संसद (पीपुल्स मजलिस) में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल हुआ है। भारत समर्थक नेता माने जाने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को केवल 15 सीट पर जीत मिली। संसद में बहुमत मिलने का मतलब है कि मुइजू की पार्टी का न केवल सांसदों पर बल्कि विधायिका पर भी नियंत्रण होगा जो कानूनों का



अनुमोदन करती है। इसमें अब तक दो परस्पर विरोधी गठबंधन थे और सरकार एवं विधायिका के बीच टकराव के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। संसदीय चुनाव में पीएनसी को मिले ‘प्रचंड बहुमत को मुइजू की चीन समर्थक विदेश नीति को मजबूत समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित इस द्वीपीय राष्ट्र के चुनाव नतीजों पर भारत और चीन, दोनों देश करीबी नजर रखे हुए थे। मुइजू (45) देश से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के अपने वादे के सहारे सत्ता में आए और नवंबर 2023 में पदभार संभालने के बाद चीन का दौरा किया तथा

बीजिंग के साथ रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में माले के संबंध प्रगाढ़ किए। संसदीय चुनाव से पहले, सोलिह की पार्टी एमडीपी ने भारत के साथ संबंध बहाल करने की हिमायत की थी। मुइजू ने कहा, ‘‘हम एक गौरवशाली राष्ट्र हैं जो संप्रभुता और स्वतंत्रता से प्रेम करता है जिसे हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भी प्रदर्शित किया है। मुइजू ने मालदीव को उपहार में दिये तीन विमानन प्लेटफॉर्म पर तैनात 88 भारतीय सैन्य कर्मियों की स्वदेश वापसी के लिए दबाव बनाया। तीन में दो बैच मालदीव से जा चुके हैं। सनडॉटएमवी समाचार पोर्टल के अनुसार, राष्ट्रपति मुइजू ने किसी

देश का नाम लिये बिना कहा कि संसदीय चुनाव यह भी साबित करता है कि मालदीव ‘‘विदेशी बल प्रयोग के बिना अपने भविष्य को चुनने के लिए स्वायत्तता चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘गुप्त एजेंडा रखने वालों के लिए भी स्पष्ट हो गया है कि मालदीव क्या चाहता है। उन्हें अधाधुनॉटकॉम ने उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘मालदीव के बाहर हर कोई...अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सभी के लिए यह अब स्पष्ट हो गया है कि हम अपने मुद्दों को खुद से करना चाहते हैं। उन्होंने अपने विजय भाषण में किसी देश का नाम नहीं लिया था। हालांकि, मुइजू और पीएनसी के अन्य नेताओं ने बार-बार आरोप लगाया था कि भारत ने अतीत में इसके आंतरिक मामलों को प्रभावित किया है। सोमवार के अपने संबोधन में मुइजू ने यह भी दावा किया कि चुनाव परिणाम इसका सबूत है कि मालदीव अपने भविष्य को गढ़ने में इस्लाम और इसके सिद्धांतों का अनुसरण करना जारी रखेगा। इस बीच, स्पीकर मोहम्मद असलम ने ऐलान किया कि संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों को 28 मई को शपथ ग्रहण दिलायी जाएगी।



सोने का उत्खनन करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे बाहर से भारी पैमाने पर खरीदना पड़ता है। पिछले 2 साल में चीन ने अन्य देशों से 2,800 टन से यादा सोना खरीदा है। यह अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के कुल स्वर्ण भंडार के एक तिहाई के बराबर है। सबसे यादा सोने का खनन करता है चीन रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भले ही किसी भी अन्य देश की तुलना में सोने का यादा खनन करता हो, लेकिन फिर भी उसे बहुत यादा आयात करने की जरूरत पड़ती है। हाल ही में शिपमेंट की गति में तेजी

आई है। चीन के चंद्र नववर्ष उपहारों का पीक सीजन है, इससे पहले आयात में उछाल आया है। यह साल के पहले दो महीनों में 2023 की तुलना में 53 फीसदी यादा है। चीन में कमजोर युआन के बावजूद चीन में सोने की मांग यादा बनी हुई है। एक प्रमुख आयातक के रूप में चीन में सोने के खरीदारों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर प्रीमियम देना पड़ता है। महीने की शुरुआत में यह बढ़कर 89 डॉलर प्रति औंस हो गया। पिछले साल का औसत 35 डॉलर रहा है, जबकि ऐतिहासिक औसत सिर्फ 7 डॉलर रहा है।

यूरोपीय संघ ने भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल शेंगेन वीज़ा नियम अपनाएं

इंटरनेशनल डेस्क- यूरोपीय आयोग ने 18 अप्रैल को भारतीय नागरिकों के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा जारी करने पर विशिष्ट नियम अपना गए हैं। भारत के लिए नव अपनाई गई वीजा कैस्केंड व्यवस्था के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के भीतर दो वीजा प्राप्त करने और वैध रूप से उपयोग करने के बाद भारतीय नागरिकों को अब दो साल के लिए वैध दीर्घकालिक, बहु-प्रवेश शेंगेन वीजा जारी किया जा सकता है। यह निर्णय प्रवासन और गतिशीलता पर ईयू-भारत कॉमन एजेंडा के तहत मजबूत संबंधों के संदर्भ में आता है, जो ईयू और भारत के बीच प्रवासन नीति पर व्यापक सहयोग चाहता है, जिसमें लोगों से लोगों के संपर्क की सुविधा प्रमुख पहलू है। यूरोपीय संघ के लिए एक भागीदार के रूप में भारत का महत्व। शेंगेन वीजा धारक को किसी भी 180-दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिनों के छोटे प्रवास के लिए शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश (जिनमें से 25 यूरोपीय संघ के राय हैं)- बेल्जियम,



बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराय, डेनमार्क, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल,

रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड और स्वीडन, साथ ही आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

मलेशिया में हवा में टकराए मिलिट्री के 2 हेलिकॉप्टर, 10 लोगों की मौत



इंटरनेशनल डेस्क: मलेशियाई नौसेना ने कहा कि मंगलवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो सैन्य हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे उनमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर नौसेना की 90वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी के लिए उत्तरी पेराक राय में एक नौसैनिक अड्डे पर प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे थे। नौसेना की

90वीं वर्षगांठ अगले महीने है। बयान के मुताबिक, दोनों हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नौसेना ने बयान में बताया कि मृतकों की पहचान के लिए शव अस्पताल भेज दिये गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कई हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर फोर्मेशन में उड़ रहे थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर दूसरे विमान के रोटर से टकरा गया, जिस वजह से दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गये।

शिकायत के बाद भी अपने बयान पर अड़े गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान समर्थक देशद्रोहियों से वोट नहीं मांगूंगा

बेगूसराय- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि वह खुले तौर पर कह रहे हैं कि वह बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में ‘‘पाकिस्तान समर्थक देशद्रोहियों%% से वोट नहीं मांगेंगे। गिरिराज सिंह भाजपा उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दो दिन पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की बिहार इकाई ने निर्वाचन आयोग से घृणा भाषण को लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय मंत्री ने 19 अप्रैल को अस्पताल भेज दिये गए हैं। सोशल कथित तौर पर कहा था कि वह ‘पाकिस्तान समर्थक राष्ट्र-विरोधियों% और जिन्हें ‘राष्ट्रवाद से समस्या है% उनसे वोट नहीं मांगेंगे। जब पत्रकारों ने आयोग से शिकायत के संबंध में गिरिराज



सिंह से प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि मैं अपने चुनाव अभियान के दौरान पाकिस्तान समर्थक राष्ट्र-विरोधियों और उन लोगों से अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा जिन्हें राष्ट्रवाद से समस्या है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि

उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर भाकपा को ऐसे लोगों के वोटों की जरूरत है, तो पार्टी को खुले तौर पर इसकी घोषणा करनी चाहिए। भाकपा ने बेगूसराय लोकसभा सीट से अवधेश राय को मैदान में उतारा है जहां 13 मई को मतदान होगा।

शिंदे ने खोले एम.वी.ए. सरकार के राज, कहा भाजपा के 4 बड़े नेताओं जेल भेजना चाहते थे उद्भव

नेशनल डेस्क- महाराष्ट्र में अब दो शिव सेनाओं के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। सियासी माहौल पहले से गरमाया हुआ है और इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन उद्भव ठाकरे की एम.वी.ए. सरकार के समय के राज खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तत्कालीन उद्भव ठाकरे सरकार ने भाजपा के शीर्ष नेताओं को जेल भेजने की साजिश रची थी, जिनमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल था। मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री शिंदे उने दावा करते हुए कहा कि महाअघाड़ी सरकार ने आशीष शेलार, गिरीश महाजन, प्रवीण दारकर और फडणवीस को जून 2022 से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की थी। मुख्यमंत्री यह भी दावा किया है कि एम.वी.ए. भाजपा के कई विधायकों को अपने पाले में लाना चाहती थी।

उद्भव खुद ही बनाना चाहते थे किंग

शिंदे का दावा है कि एम.वी.ए. का गठन पहले से ही तैयार योजना के तहत किया गया था और उद्भव का सपना सी.एम. बनने का था। उन्होंने कहा कि अपने पिता की तरह किंगमेकर बनने के बजाए उद्भव खुद ही किंग बनना चाहते थे। शिंदे जून-जुलाई 2022 में अविभाजित शिवसेना से अलग हो गए थे। सी.एम. ने दावा किया है कि एम.वी.ए. सरकार में मंत्री रहते हुए उन्हें लगातार अपमान का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ठाकरे परिवार की तरफ से काम में दखल दिए जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भले ही मैं शहरी विकास मंत्री था, लेकिन मुझे कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। बिना किसी अधिकार के आदित्य ठाकरे उनके काम में दखल देते थे।

आदित्य ठाकरे का था सरकार में दखल

आदित्य ठाकरे के बारे में उन्होंने कहा कि कई मौकों पर वह शहरी विकास, एम.एम.आर.डी.ए., सिडको और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की बैठक लेते थे। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के टूटने से पहले ठाकरे उनसे शहरी विकास विभाग लेने की योजना तैयार कर रहे थे।

अधीर रंजन चौधरी के लिए बड़ी चुनौती बने यूसुफ पठान

नेशनल डेस्क- पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) ने गुजरात से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार कर इस सीट से पांच बार सांसद रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जानकारों की माने तो इस सीट पर कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के लिए ये चुनाव जीतना आसान



नहीं होने वाला है। इस सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा।



रिपोर्ट के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी 1999 से इस सीट से लगातार सीट हासिल

करते आ रहे हैं। यूसुफ पठान के अलावा अधीर रंजन का मुकाबला भाजपा के निर्मल कुमार साहा से भी है, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय डॉक्टर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और तृणमूल 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन 7 में से 6 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और केवल एक सीट-बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र में उसे भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार

पांच जीत के बावजूद अधीर रंजन बहरामपुर में कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनाए रखने में विफल रहे हैं। पार्टी न केवल विधानसभा चुनावों में पिछड़ गई, बल्कि पिछले पंचायत और निकाय चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि, तृणमूल उम्मीदवार यूसुफ पठान ने बहरामपुर में मतदाताओं के एक वर्ग के बीच कुछ उत्साह पैदा किया है, लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर संदेह व्यक्त किया है कि इसका कितना हिस्सा वोट में तब्दील होगा।